(c) what are the reasons for not getting the entire work done through D.A.V.P.; and

(d) whether Government propose to make a policy that entire advertising/publicity work should be got done through D.A.V.P. only; if so, by when; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) The amount spent by ITDC on account of publicity work through D.A.V.P. and private agencies is as under:—

(Rs. in lakhs)

Year	DAVP	Pvt. agencies	Others
*1984-85	NIL	44.88	0·36
1985-86	NIL	40·41	1·50
1986-87	NIL	52·23	1·39

*Figures available for full financial year.

(b) Names and addresses of the private agencies and amount given to each of them are as follows:—

(Rs. in lakhs)

	1984-85	1985-86	1986-87
Advertising & Sales Promotion, Padma Tower, Rajindra Place, New Delhi	13·87	11·58	18·55
Aksbara Advertising, Meghdoot, 94, Nehru Place, New Delhi	31·01	28·83	33·68

(c) and (d) In the year 1984-85, ITDC had hired the services of private agencies on the approved panel of D.A.V.P. However, after considering the matter the practice of accrediting advertising agencies for public sector undertakings, autonomous bodies etc. has since been discontinued by the D.A.V.P. w.e.f. 8th November, 1985.

"रामायण" धारावाहिक के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

2499. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "रामायण" धारावाहिक के प्रसारण के पूर्व और इस धारावाहिक के आरम्भ होने के पश्चात् दूरदर्शन की विज्ञापनों के माध्यम से होने वाली आय में तुलनात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान दूरदर्शन की आय में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से दूरदर्शन की सकल आय में वृद्धि की अपेक्षा विभिन्न कारणों से की जाती है जैसे मार्च, 1987 से विज्ञापन दरों में संशोधन, जनवरी, 1987 से रामायण" धारावाहिक का टेलीकास्ट

शुरू करना इन कारणों में से एक हो सकता है । अतः "रामायण" धारावाहिक को शुरू करने से पहले और बाद में हुई वृद्धि की केवल इसी धारावाहिक के बारे में तुलना करना संभव नही है ।

(ख) वर्ष 1987–88 के संशोधित अनुमानों में विज्ञापनों से दूरदर्शन का सकल राजस्व 140 करोड़ रुपए है और वर्ष 1988–89 के लिए बजट अनुमान 142 करोड़ रुपए है, जो 2 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है ।

नशाबंदी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने संबंधी केन्द्रीय समिति

2500. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नशाबन्दी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने संबंधी केन्द्रीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) मद्य निषेध और नशीले पदार्थों से सम्बद्ध केन्द्रीय समिति की 3 फरवरी, 1988 को हुई बैठक में की गई सिफारिशें संलग्न हैं [देखिए परिशिष्ट सं.एक्सएलवी, अनुपत्र सं० 95]

(ख) समिति की सिफारिशें, राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों को उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई है ।

Feed-stock for fertilizer plant under the Gujarat State Fertilizer Corporation

2501. SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken on the feedstock for the proposed fertilizer plant under the Gujarat State Fertiliser Corporation;

(b) whether it will be gas based or naphtha based; and

(c) if answer to part (a) above be in the negative, by when a decision is expected to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The feedstock for the proposed 1350 tpd ammonia plant of M/s. Gujarat State Fertilizer Company is naphtha.

Stoppage of undue expulsion of Members of Co-operative Group Housing Societies

2502. SHRI F. M. KHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the Co-operative Group Housing Societies in Delhi frequently resort to expulsion of their members for non-payment of dues, where the members have applied for house-building advances in their respective Government/State Government offices; and

(b) if so, what remedial steps Government are taking to issue instructions to the Cooperative Group Housing Societies to stop such undue expulsion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha